

महाराष्ट्र के सबक

महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में भी पार्टी न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीत कर लाई बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए आवश्यक बहुमत भी आसानी से सुनिश्चित कर लिया। मगर राजनीति में वोट और सीटें ही नहीं, सहयोगी दल भी अहमियत रखते हैं।

अमिता चौधरी

महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी ने जब रविवार को राज्यपाल से साफ-साफ कह दिया कि वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना सक्रिय हुई। कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाने की उसकी कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है यह अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा, लेकिन अपने आप में यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं कि केंद्र, राज्य और मुंबई महानगरपालिका तीनों स्तरों पर सत्ता में शामिल दो राजनीतिक दल सीट बंटवारे का समझौता करने के बाद साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, स्पष्ट बहुमत हासिल करते हैं और इसके बावजूद सरकार नहीं बना पाते।

गौर करने की बात है कि ये दोनों

पार्टियां तब से गठबंधन में हैं जब देश में गठबंधन का दौर शुरू भी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में चली सहानुभूति लहर के चलते 1984 के आम चुनाव में बीजेपी दो लोकसभा सीटों तक सिमट कर रह गई थी। तब बीजेपी को राजनीति में अछूत माना जाता था। कोई भी दल उससे हाथ मिलाने को आसानी से तैयार नहीं होता था। ऐसे में बाला साहेब ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और बीजेपी ने एक-दूसरे का हाथ थामा। 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़े। इस बीच कांग्रेस का आधार सिमटता गया और देश में गठबंधन की सरकारों का युग शुरू हुआ।

वाजपेयी की अगुआई में एनडीए के दलों ने पहली बार केंद्र में स्थिर सरकार

देकर साबित किया कि गठबंधन का मतलब अनिवार्यतः मध्यावधि चुनाव नहीं होता। हालांकि वाजपेयी को भी गठबंधन के घटक दलों की ओर से धमकियों-चेतावनियों का सामना करते रहना पड़ता था, लेकिन 'गठबंधन धर्म' का पालन करते हुए वह देश को टिकाऊ सरकार देने में कामयाब रहे। उसके बाद कांग्रेस ने भी यूपीए गठबंधन की सरकार दस साल तक सफलतापूर्वक चलाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की कामयाबी यह रही कि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने के बावजूद इसने पूर्ण बहुमत हासिल किया और पांच साल बाद अगले चुनाव में उस बहुमत को और बढ़ा लिया। इस दौरान एनडीए के घटक दलों

की ओर से ये शिकायतें आती रहीं कि बीजेपी नेतृत्व उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं देता, लेकिन अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी ने चुनाव-दर-चुनाव साबित किया कि घटक दलों के असंतोष का उसके वोटों पर या सीटों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में भी पार्टी न केवल सबसे ज्यादा सीटें जीत कर लाई बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए आवश्यक बहुमत भी आसानी से सुनिश्चित कर लिया। मगर राजनीति में वोट और सीटें ही नहीं, सहयोगी दल भी अहमियत रखते हैं। महाराष्ट्र में एक जीती हुई बाजी हारकर बीजेपी को यह सबक मिला है। देखना होगा कि वह इस सबक को कितनी गंभीरता से लेती है और आगे अपने रवैये में किस तरह का बदलाव लाती है।

सही और गलत

चन्द्र गुप्ता

चुनाव का विकल्प हमेशा 'अच्छे' और 'बुरे' के बीच नहीं होता। अक्सर ये विकल्प 'बुरा' और 'बहुत बुरा' के बीच होता है। विकल्प से सामना होने पर चुनाव करना हमारे लिए बहुत दुखदायी हो जाता है। अनिर्णय की स्थिति की खासियत यह है कि यह हममें से अधिकतर लोगों को बहका देती है। वहां विकल्प होते हैं लेकिन वो अल्पकालिक और अप्रसांगिक होते हैं, उदाहरण के लिए सप्ताह के अंत में देखने जाने वाली किसी फिल्म का चुनाव करना।

कुछ ऐसे विकल्प भी होते हैं जो जीवन को प्रभावित कर सकते हैं जैसे, कौन सी नौकरी करनी है और किससे शादी करनी है। दैनिक जीवन के ज्यादातर चुनाव इन्हीं दोनों चरम सीमाओं के बीच आते हैं। अगर चुनाव कर लिया गया है और वह सही नहीं है, तब भी उसे एक अनुभव के तौर पर लें जो आपको भविष्य में लाभ पहुंचा सकता है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

मेडिकलेम का फर्जीवाड़ा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने लोकसभा को बताया है कि आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह ट्रैक पर है और देश के 10.74 करोड़ परिवार अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया था कि अभी देश में 19,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एबीएचडब्ल्यूसी) चल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक साल 2019-20 के अंत तक ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 40,000 कर दी जाएगी। यह योजना देश के आम गरीब नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसलिए इसे लेकर सरकार का उत्साह समझ में आता है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के इन वक्तव्यों में इस योजना से जुड़े चिंताजनक पहलुओं की कोई झलक नहीं मिलती। इनमें सबसे खतरनाक है अस्पतालों द्वारा इस योजना को जरिया बनाकर की जा रही धोखाधड़ी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (एनएचए) की एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड सहित कई राज्यों में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत चल रही धोखाधड़ी के हैरतअंगेज मामले पकड़े गए हैं। कुछ मामलों में तो पुरुषों के गर्भाशय को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाना दिखाया गया है, जबकि गर्भाशय केवल स्त्रियों में होता है, पुरुषों में इसके होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मरीज की जब पर इसका ज्यादा बोझ भले न पड़ता हो, पर उसके शरीर की दुर्गति हो जाती है। यह गोरखधंधा अब मध्यमवर्गीय लोगों से आगे बढ़कर बरास्ते आयुष्मान गांवों के गरीब परिवारों तक पहुंच रहा है तो उनकी दशा की कल्पना ही की जा सकती है। बेहतर होगा कि सरकार अभी अपनी ताकत आयुष्मान भारत योजना को देशव्यापी बनाने के बजाय इसके छेद बंद करने पर लगाए।

गणना की जवाबदेही वाले अफसरों का कहना है कि एक और डेढ़ साल के बाघ के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता, लिहाजा गणना की न्यूनतम आयु एक साल कर दी गई है।

बढ़ रहे हैं बाघ

संजय भट्ट

अभी जब रोज ही वन्य जीवों को लेकर कोई न कोई बुरी खबर पूरी दुनिया से आ रही है, तब भारत में बाघों की संख्या में तेज बढ़ोतरी की सूचना पर्यावरण प्रेमियों का हौसला बढ़ाने वाली है। विश्व बाघ संरक्षण दिवस (29 जुलाई) पर स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल देश में कुल 2,967 बाघ हैं। यह संख्या 2014 में हुई पिछली गणना से लगभग एक तिहाई ज्यादा है, जबकि 2006 में बाघ बचाने का संकल्प लिए जाते वक्त की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। इसमें एक तकनीकी पेच यह है कि बाघों की पिछली गिनती में डेढ़ साल या इससे ज्यादा उम्र वाले बाघ ही गिने गए थे, जबकि इस बार एक साल तक की उम्र वाले बाघ गिने गए हैं। गणना की जवाबदेही वाले अफसरों का कहना है कि एक और डेढ़ साल के बाघ के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता, लिहाजा गणना की न्यूनतम आयु एक साल कर दी गई है। इसके डेढ़ साल रखने की वजह यह बताई गई थी कि इस उम्र में आकर बाघ आत्मनिर्भर हो जाता है। बहरहाल, यह सिर्फ एक तकनीकी मामला है। बाघ संरक्षण की दृष्टि से बुरी खबर यह है कि तीन भारतीय बाघ अभयारण्यों में सारी कोशिशों के बावजूद एक भी



बाघ नहीं खोजा जा सका है।

एक बड़ी समस्या बाघों के रहने की जगह की है। अभी भारत में बाघ अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख 80 हजार वर्ग किलोमीटर है, जबकि गिने गए लगभग तीन हजार बाघों को रहने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर प्रति बाघ के हिसाब से 6 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग दोगुनी जगह की जरूरत पड़ेगी। जगह कम होने के तीन असर देखे जाते हैं। एक तो बाघ आपस

में ही लड़कर मारे जाते हैं। दूसरे, अपनी खुराक पूरी करने के लिए वे इंसानी बस्तियों में जाते हैं और लोगों के गुस्से का शिकार बनते हैं। तीसरे, कई बार उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता और वे लगातार भुखमरी से ग्रस्त होकर कहीं मरे पाए जाते हैं। ये सारे कारक चीनी बाजारों में बाघों के अंगों की तस्करी करने वाले फंदामार शिकारियों के अलावा हैं, जिन्होंने राजस्थान जैसे बाघों के गढ़ में इनकी जड़ ही तोड़ दी। ध्यान रहे, बाघों को जिंदा रखना हमारी सहज सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बाघ मर जाएगा, लेकिन न तो घास खाएगा, न चूहा-गिलहरी मारकर गुजारा करेगा। उसके जिंदा रहने के लिए जंगल में हिरन, नीलगाय और सूअर जैसे मंझोले कद के शाकाहारी जानवरों का बड़ी तादाद में होना जरूरी है। लेकिन इन्हें पाल सकने वाले घने जंगलों का न तो देश की बढ़ती आबादी से कोई मेल बनता है, न ही दिनोंदिन खड़ी होती आवासीय कॉलोनियों और सड़क, रेलवे, 'नदी जोड़ों' जैसी परियोजनाओं से, जिन्हें समवेत रूप से हम 'विकास' मानने लगे हैं। इन दबावों के बीच अगर हम सचमुच बाघ बचाने में कामयाब होते हैं तो दुनिया मानेगी कि भविष्य को लेकर हमारी समझ एकांगी नहीं है।

सूटोपु नवताल- 5141				****			
4				1	8		
		6	7				2
			8				
	8	5					
	2		1			7	
						3	5
					5		
1			4	7			
9	6						4

सूटोपु नवताल- 5140 का हल			
1	9	7	4
4	5	3	9
2	6	8	7
5	3	1	2
9	2	4	8
7	8	6	5
6	7	2	7
3	4	9	6
6	7	2	1
8	1	5	3
8	1	5	3

अपना ब्लॉग

यहां अंधविश्वास के खिलाफ विज्ञान है हथियार

श्रीरथ खरे। यदि शिक्षक प्रयोगधर्मी, रचनात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से शिक्षण कार्य करते हैं तो स्कूल के हर लक्ष्य को साधा जा सकता है। महाराष्ट्र में वर्धा जिले की गजानन नगर प्राथमिक शाला द्वारा हासिल उपलब्धि इसी बात की पुष्टि करती है। यहां के शिक्षक और प्रयोगधर्मी हैं और यह स्कूल अपनी प्रयोगधर्मिता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, यह स्कूल खास तौर पर विज्ञान विषय को बहुत अधिक महत्व देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि यहां हर वर्ष विज्ञान से संबंधित सभी कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस दौरान शिक्षक और जानकार बच्चों को विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बाता दें कि इस प्राइमरी स्कूल में पहली से चौथी तक के कुल 62 बच्चों के लिए तीन शिक्षक हैं। यह स्कूल वर्धा शहर के बहुत करीब है, इसलिए इस क्षेत्र के कई बच्चे शहर के निजी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में जाते हैं। यहां आने वाले ज्यादातर बच्चों के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए बच्चों के दैनिक जीवन के विषय उठाती हैं।

